

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियां,

उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग- 1

देहरादून

दिनांक 23 मार्च, 2007

विषय- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना  
उधमसिंहनगर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5529/ आई०सी०डी०पी०/2006-07 दिनांक 18.1.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना उधमसिंहनगर की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए रु० 1.80 लाख (एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) अनुदान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी। उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है-

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में नियमानुसार समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) स्वीकृत अनुदान की धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के पत्र संख्या 3-29/2000-आई०सी०डी०पी०(81-82) दिनांक 27.7.2006 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार व्यय किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि निगम की उक्त परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय-समय पर प्राप्त शर्तों के अनुरूप नियंत्रित होगी।
- (4) इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की होगी।
- (5) आवश्यक उपयोग प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथा समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को नैगारिक रूप से अवगत कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना एवं भौतिक प्रगति की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
- (6) पैरा-1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जायेगी। लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

2. इस शासनादेश के प्रस्तर-1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों के अनुपालन विभागों /उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/ जैसा भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मागले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।
3. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत 2425-सहकारिता आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-04-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)-00-20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।
4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता/अनुदान की धनराशि रू० 1.80 लाख (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) की प्राप्तिर्षी लेखाशीर्षक 0425-सहकारिता-800-अन्य प्राप्तिर्षी-03-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।
5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 1016/वि०अनु०-4/03 दिनांक 21.3.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

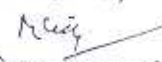
भवदीय

(डा० रणवीर सिंह)  
सचिव,

संख्या 157(1) XIV-1/2007, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-4/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4-सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 3-29/2000 -आई० सी० डी०पी० (81-82) दिनांक 27.7.2006 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
7. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, देहरादून।
8. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय प्रशासन।
9. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड उधमसिंहनगर।
10. सचिव/ महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि० उधमसिंहनगर।
11. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,  
  
(बी०आर०टम्टा)  
अपर सचिव।